

SHRI HARI KISHORE SINGH : Khadi has proved to be a favourite with Hippies from Western countries. What does the Government propose to do to popularise khadi among the younger generation in Western countries, specially in Western Europe and America.

SHRI A. C. GEORGE : Regarding promotion of khadi use among the younger generation, I may submit that the Government of India is quite alive to this problem and enough is spent on promotion. As regards its popularisation among Hippies, I leave it to the hon. Member.

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूँ कि जो खादी हम निर्यात करते हैं, वह अपने यहां के भावों से बहुत कम में निर्यात करते हैं, क्या यह सत्य है ? यदि हाँ तो इसका क्या कारण है ?

श्री एल. एन. मिश्र : यह सत्य नहीं है कि यहां के भाव से कम मात्र में हम निर्यात करते हैं। यह बात सही है कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम भेजने वालों को कुछ सुविधाएं देते हैं, लेकिन यह बात सही नहीं है कि उसके दाम में कमी कर के निर्यात करते हैं। यह बात सत्य नहीं है कि यहां जो दाम है वह विदेशों से ज्यादा है या विदेशों की कीमत यहां से कम है।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Several measures have been taken to evolve a new designs and all that for making Khadi more export-oriented. May I know whether the person who are engaged in this type of designing and all that are competent enough and whether any training is being contemplated so that Khadi products become more popular in other countries ?

SHRI A. C. GEORGE : The Khadi and Village Industries Commission is directly concerned with it. Our information is that a lot of research is going on and quite competent people are engaged in it.

SHRIMATI MUKUL BANERJEE : Is the Government aware of the fact that in

Calcutta the Khadi Gramodyog Bhavan, in spite of the stocks they are having, are not often bringing out all the cloth because some businessmen have started taking interest and are trying to take over the Khadi industry by maligning the Government ?

SHRI A. C. GEORGE : I made it plain that the production side of Khadi is the direct concern of the Industrial Development Department. This has not been brought to our notice.

Ernakulam Telephone Exchange

*1570. **SHRI A. K. GOPALAN :** Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Class III and Class IV employees working in the Ernakulam Telephone Exchange (Kerala) went on strike during the month of July in support of their demands ;

(b) if so, the main demands of the employees ; and

(c) the steps taken by Government to meet their demands ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise

SHRI A. K. GOPALAN : May I know whether it has come to the notice of the Government that there was an agitation in the month of July by Class III and Class IV employees and there was some compromise between authorities and the workers and some demands were conceded and, if so, what are the demands conceded?

SHRI H. N. BAHUGUNA : I have only the information about the specific Question of strike during the period mentioned by the hon. Member. I have no other information available with me.

SHRI A. K. GOPALAN : May I know whether it has come to the notice of

the Government or whether the Government knows as to how many of those employees who had been victimised as a result of September 1968 strike are still out of job? I would like to know how many have been taken and if anybody is still out and has not been taken, whether their cases will be considered?

SHRI H. N. BAHUGUNA : This is again a separate question concerning the 1968 strike.

SHRI VAYALAR RAVI : May I know from the hon. Minister whether there is any complaint of intimidation and assault by the N. F. P. T. Union against other Unions in Kerala?

SHRI H. N. BAHUGUNA : The question is not relevant here.

MR. SPEAKER : Yes.

दिल्ली में शुष्क पत्तन

*[57]. श्री आर. वी. बड़ें : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शुष्क पत्तन बनाने के प्रस्ताव पर सर्वप्रथम कब विचार किया गया था ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अभी कौन-कौन सी औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल. एन. मिश्र):

(क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल रखा जाता है।

विवरण

दिल्ली में एक शुष्क पत्तन स्थापित करने के लिए एक प्रस्थापना सरकार को जून, 1965 में मिली थी, लेकिन यह प्रस्थापना स्वीकार्य नहीं पाई गई। इसके बाद, दिल्ली प्रशासन ने एक समिति गठित की, जिसकी रिपोर्ट में

जो जनवरी, 1967 में प्रस्तुत की गई थी, तीन वैकल्पिक योजनाएं दी गई थीं। उसके बाद भारत सरकार ने एक अन्तः मंत्रालय कार्यकारी दल स्थापित किया, जिसे दिल्ली में एक शुष्क पत्तन की स्थापना के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। कार्यकारी दल ने मई, 1970 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस पर तत्काल ध्यान दिया जा रहा है। सम्भावना है कि सरकार निकट भविष्य में ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लेगी।

श्री आर. वी. बड़ें : जो विवरण रखा गया है उसमें कहा है कि 1965 में और उसके बाद फिर 1967 में दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने उनके पास रिपोर्ट भेजी थी, सन् 1970 तक वह आपके पास पड़ी रही। उसके बाद आपने एक मिनिस्टीपरिल वर्किंग ग्रुप नियुक्त किया था.....

MR. SPEAKER : The rules on supplementaries are that there should be no giving of information yourself. You ask a direct question.

श्री आर. वी. बड़ें : मिनिस्टर्स वर्किंग ग्रुप ने आपके पास 1970 में रिपोर्ट भेजी है, तो मेरा प्रश्न यह है कि मिनिस्टर्स वर्किंग ग्रुप के पास वह तीन साल तक रिपोर्ट क्यों पड़ी रही और तीन साल तक आपने क्या किया ?

श्री एल. एन. मिश्र : जी हां, रिपोर्ट आई और देखा गया कि वह कुछ ज्यादा उत्साहवर्द्धक नहीं थी, ऐसा लगता था कि यह नहीं हो सकता है। फिर हम लोगों ने एक इंटर मिनिस्टीरियल वर्किंग ग्रुप बनाया। 1970 में उसकी रिपोर्ट आई। उसके बाद 1971 में एक इंटर डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई है और उन्होंने सिफारिश की है। इसकी जांच हो रही है कि इसकी सम्भावना हो सकती है या नहीं कि दिल्ली में ड्राई पोर्ट बनाया जाय। यह अप्रैल 1971 की बात है।